राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह
RAJIV RANJAN SINGH ALIAS LALAN SINGH

सत्यमेव जयते

पंचायती राज मंत्री
और मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री
भारत सरकार
Minister of Panchayati Raj and
Minister of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying
Government of India

DO. No.27872 MIN PR&FAHD/2026

MESSAGE

On the proud occasion of the 76th Republic Day, I extend my warm greetings and best wishes to all Elected Representatives and Panchayat Functionaries across the country.

2. Republic Day reminds us that the strength of our Republic lies in the participation of every citizen and in the effectiveness of institutions closest to the people. The Hon'ble Prime Minister has repeatedly emphasized that India's rapid development is possible only when its villages are strong and self-reliant. Accordingly, India's transformation into a developed and strong nation by 2047 will be built from the bottom up, with empowered Gram Panchayats at its foundation.

3. Panchayati Raj Institutions are central to the constitutional vision of participatory democracy, inclusive development, and Gram Swaraj- village self-governance. Panchayats serve as the first point of contact for rural citizens, addressing everyday needs, resolving grievances, and ensuring access to essential services. With 50% reservation for women, Panchayats have also emerged as the torchbearers for women's leadership and empowerment, enabling women to actively shape local development priorities.

4. This empowerment is further strengthened through initiatives that place women and communities at the centre of growth, whether through Self Help Groups, livelihood missions, or innovative programmes such as Drone Didi, which symbolise how technology and skills can transform rural women into agents of economic change. Together, these efforts reflect the Prime Minister's vision of Atmanirbhar Bharat, where villages become engines of self-reliant growth rather than recipients of assistance alone.

5. The focus of the Government on infrastructure and property rights has also fundamentally strengthened Panchayats. Initiatives such as SVAMITVA have provided legal certainty, economic security, and new opportunities for rural households. At the same time, the goal is towards ensuring all Gram Panchayats have dedicated Panchayat buildings, digital

Room No. 234, B- Wing, Krishi Bhawan, Dr. Rajendra Prasad Road, New Delhi-110 001 (India)
Ph. +91 11-23380780/81/82 Fax: +91 11- 23380783 Resi. 011-23782781/82

tools, and Internet connectivity to help transform Panchayats into efficient, modern institutions capable of delivering services with dignity and transparency.

6. Today marks a transformative moment with the launch of ***PANCHAM- Panch****ayat Assistance & **Messaging** chatbot*, a pioneering digital initiative designed to place the power of information, guidance, and decision-support directly in the hands of Panchayat Representatives and Functionaries. PANCHAM is envisioned as a governance companion for Panchayats, supporting them in understanding rules, procedures, entitlements, and workflows in a simple and contextual manner. By enabling quick access to reliable information at the point of action, PANCHAM significantly reduces delays, procedural ambiguity, and dependence on informal channels.

7. More importantly, PANCHAM establishes, for the first time, a direct digital bridge between over 30 lakh Elected Representatives and Panchayat Functionaries and the Government of India. This two-way connectivity ensures that field-level challenges, implementation bottlenecks, and citizen concerns are communicated swiftly to decision-making centres, while policy guidance and advisories reach Panchayats without delay. Such real-time feedback loops will enable faster decision-making, responsive course correction, and more effective service delivery at the grassroots.

8. PANCHAM also strengthens institutional capacity and confidence at the Panchayat level. By standardizing guidance and processes, it promotes uniform interpretation of rules, enhances accountability, and supports transparent decision-making. This directly contributes to the Prime Minister's vision of Minimum Government, Maximum Governance, where systems are simplified, and governance becomes predictable, citizen-centric, and outcome-oriented.

9. As we move towards Viksit Bharat @2047, I call upon every Panchayat, every representative, and every functionary to carry forward the vision of our forefathers and the Hon'ble Prime Minister of Gram Swaraj, Minimum Government, Maximum Governance, and people-led development. Let us work together to transform villages into vibrant, self-sufficient units of growth, with Panchayats as crucial engines of change driving India's overall development.

10. On this Republic Day, let us renew our collective resolve to strengthen grassroots democracy, deepen citizen participation, empower women and communities, and uphold the constitutional values that guide our nation.

(Rajiv Ranjan Singh)

राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह
RAJIV RANJAN SINGH ALIAS LALAN SINGH

सत्यमेव जयते

पंचायती राज मंत्री
और मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री
भारत सरकार
Minister of Panchayati Raj and
Minister of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying
Government of India

DO. No.27872.MIN PR&FAHD/20.2.6

संदेश

76वें गणतंत्र दिवस के गौरवपूर्ण अवसर पर, मैं देश भर की पंचायतों के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों और पंचायत पदाधिकारियों को हार्दिक शुभकामनाएँ एवं बधाई देता हूँ।

2. गणतंत्र दिवस हमें याद दिलाता है कि हमारे गणराज्य की असली ताकत हर नागरिक की भागीदारी और जनता के सबसे नज़दीक काम करने वाली संस्थाओं की प्रभावशीलता में है। माननीय प्रधानमंत्री ने बार-बार कहा है कि भारत का तेज़ विकास तभी संभव है, जब उसके गाँव मज़बूत और आत्मनिर्भर हों। इसी सोच के अनुसार, 2047 तक भारत को एक विकसित और सशक्त राष्ट्र बनाने की नींव जमीनी स्तर, यानी सशक्त ग्राम पंचायतों के माध्यम से रखी जाएगी।

3. पंचायती राज संस्थाएँ सहभागी लोकतंत्र, समावेशी विकास और ग्राम स्वराज—यानी गाँवों द्वारा स्वयं शासन—की संवैधानिक सोच का केंद्र हैं। पंचायतें, ग्रामीण नागरिकों के लिए शासन का पहला संपर्क बिंदु होती हैं, जहाँ रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा किया जाता है, शिकायतों का समाधान होता है और आवश्यक सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित की जाती है। महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण के माध्यम से पंचायतें 'महिला नेतृत्व और सशक्तिकरण' की मजबूत आधारशिला भी बनी हैं, जिससे महिलाएँ स्थानीय विकास की प्राथमिकताओं को तय करने में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं।

4. यह सशक्तिकरण उन पहलों से और मजबूत हुआ है, जिनमें महिलाओं और समुदायों को विकास के केंद्र में रखा गया है—जैसे स्वयं सहायता समूह, आजीविका मिशन और *ड्रोन दीदी* जैसे नवाचारी कार्यक्रम। ये पहल दिखाती हैं कि कैसे तकनीक और कौशल ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक बदलाव का अगुवा बना सकते हैं। ये सभी प्रयास मिलकर 'आत्मनिर्भर भारत 'की उस सोच को आगे बढ़ाते हैं, जहाँ गाँव केवल सहायता लेने वाले नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर विकास के केंद्र बनते हैं।

5. बुनियादी ढाँचे और संपत्ति अधिकारों पर सरकार के विशेष ध्यान से पंचायतें और अधिक मज़बूत हुई हैं। *स्वामित्व* जैसी पहल से ग्रामीण परिवारों को कानूनी सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और नए अवसर मिले हैं। साथ ही यह लक्ष्य रखा गया है कि हर ग्राम पंचायत के पास अपना पंचायत भवन, डिजिटल उपकरण और बेहतर इंटरनेट

Room No. 234, B- Wing, Krishi Bhawan, Dr. Rajendra Prasad Road, New Delhi-110 001 (India)
Ph. +91 11-23380780/81/82 Fax: +91 11- 23380783 Resi. 011-23782781/82

कनेक्टिविटी हो, ताकि पंचायतें सम्मान और पारदर्शिता के साथ सेवाएँ देने वाली आधुनिक और सक्षम संस्थाएँ बन सकें।

6. आज एक महत्वपूर्ण बदलाव का क्षण है, जब *PANCHAM – **Panch**ayat **A**ssistance & **M**essaging chatbot* का शुभारंभ किया जा रहा है। यह एक अनूठी डिजिटल पहल है, जिसका उद्देश्य पंचायत प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के हाथों में सीधे जानकारी, मार्गदर्शन और निर्णय लेने में सहायता देना है। PANCHAM को पंचायतों के लिए एक डिजिटल साथी के रूप में तैयार किया गया है, जो नियमों, प्रक्रियाओं, अधिकारों और कार्यप्रणाली को सरल और संदर्भ के अनुसार समझने में मदद करेगा। सही समय पर विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध कराकर यह देरी, भ्रम और अनौपचारिक माध्यमों पर निर्भरता को कम करता है।

7. इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि PANCHAM पहली बार 30 लाख से अधिक निर्वाचित जनप्रतिनिधियों और पंचायत पदाधिकारियों को सीधे भारत सरकार से जोड़ता है। यह दो-तरफ़ा डिजिटल संपर्क ज़मीनी स्तर की समस्याओं, कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाइयों और नागरिकों की चिंताओं को तेज़ी से निर्णय लेने वाले स्तर तक पहुँचाता है, वहीं नीतिगत दिशा-निर्देश और सलाह, बिना देरी के पंचायतों तक पहुँचते हैं। इस तरह की त्वरित प्रतिक्रिया व्यवस्था से तेज़ निर्णय, समय पर सुधार और जमीनी स्तर पर बेहतर सेवा वितरण संभव होगा।

8. PANCHAM पंचायत स्तर पर संस्थागत क्षमता और आत्मविश्वास को भी मजबूत करता है। नियमों और प्रक्रियाओं को एक समान तरीके से समझाने के माध्यम से यह जवाबदेही बढ़ाता है और पारदर्शी निर्णय लेने में सहायता करता है। इससे प्रधानमंत्री की "न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन" की सोच को बल मिलता है, जहाँ व्यवस्थाएँ सरल होती हैं और शासन अधिक स्पष्ट, नागरिक-केंद्रित और परिणाम आधारित बनता है।

9. *विकसित भारत @ 2047* की ओर बढ़ते हुए, मैं हर पंचायत, हर जनप्रतिनिधि और हर पदाधिकारी से आह्वान करता हूँ कि वे ग्राम स्वराज, 'न्यूनतम सरकार–अधिकतम शासन' और 'जन-नेतृत्व वाले विकास' की उस सोच को आगे बढ़ाएँ, जिसकी कल्पना हमारे पूर्वजों और माननीय प्रधानमंत्री ने की है। आइए, मिलकर गाँवों को आत्मनिर्भर और सशक्त विकास इकाइयों में बदलें, जहाँ पंचायतें भारत के समग्र विकास को आगे बढ़ाने वाली परिवर्तन की प्रमुख शक्ति बनें।

10. इस गणतंत्र दिवस पर, आइए हम सब मिलकर जमीनी लोकतंत्र को मजबूत करने, नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने, महिलाओं और समुदायों को सशक्त बनाने और हमारे संविधानिक मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराएँ।

(राजीव रंजन सिंह)